लखनऊ चलो

स्थान : गाँधी भवन, रेजीडेंसी रोड, कैसरबाग़ लखनऊ

तारीख : 10 मई, 2017, समय : सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक

संघर्षशील साथियो! 10 मई सन् 1857 को आज से ठीक 160 साल पहले कुछ जाबांज भारतीय सिपाहियों ने आज़ादी की लड़ाई का पहला बिगुल फूंका था और आज ही के दिन अत्याचारी ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी सुलग उठी थी। बगावत की इसी चिंगारी से मेरठ से लेकर दिल्ली तक बगावत के शोले भड़क गए। यह हिन्दुस्तान की आज़ादी की पहली जंग थी।

आज़ादी के लिए अपने पुरखों द्वारा लड़ी गयी इस पहली जंग की विरासत को अपने दिलों में समेटे हुए इसके ठीक 160 साल बाद हम एक बार फिर उ.प्र. की राजधानी लखनऊ में जुटेंगे। हिन्दुस्तान की यह आज़ाद आवाम एक बार फिर अपने मुल्क और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता जताएंगे। यह आवाम एक बार फिर मुल्क के संविधान में मौजूद मूल्यों को बचाने की कसम खाएगी और हर तरह के अत्याचार से लड़ने का अपना बुलंद इरादा दोहराएगी।

दरअसल पिछले कुछ महीनों से गुंडों की टोलियों ने इस मुल्क की पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। वे खाने-पीने और प्रेम करने की पसंदगी की बुनियाद पर लोगों की सरे-आम हत्याएं कर रहे हैं। क्या हमारे इस मुल्क का संविधान ऐसे अराजक माहौल की इजाज़त देता है।

इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि कुछ लोग अपने ही देशवासियों की इसलिए पीट-पीट कर हत्या कर देते हैं कि उनका खाना उन्हें पसंद नहीं है। वे उन्हें इसलिए मार देते हैं कि उनका कारोबार उन्हें पसंद नहीं है। संविधान में निहित कानून के शासन के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है।

अपनी पसंद से दोस्ती करने या रिश्ता तय करना अब इस देश में गुनाह बनता जा रहा है। नौजवानों और महिलाओं को इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। इसलिये आज हमारा मुल्क हिन्दुस्तान एक पुलिसिया राष्ट्र और अराजक गणराज्य में तब्दील होता जा रहा है।

आइए ! आज के दिन हमसब एकजुट होकर इस देश में हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंसाफ सुनिश्चित कराने की कसम खाएं। इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे पर ही भारतीय गणराज्य की एकता और अखंडता टिकी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर इस देश की आवाम की आज़ादी बेमानी है। घूमने-फिरने या घुलने-मिलने की आजादी के बगैर कैसा आज़ाद भारत।

यह एक बार फिर लोगों के हक और आजादी के लिए लड़ने का इरादा जताने का वक्त है। ताकि इस देश की औरतें, लड़कियां, लड़के और आदमी आज़ादी और गरिमा की जिंदगी जी सकें। ताकि इस देश के कामगार, किसान, आदिवासी, दलित और बहुजन को उनकी मेहनत का सिला मिले। उन्हें रोज़ी-रोज़गार मिले। जिंदगी में तरक्की का मौका मिले।

ताकि इस देश के मुस्लिमों, हिंदुओं, इसाइयों, सिखों, जैनियों, यहूदियों समेत हर धर्म के लोगों को जीने का हक और अपनी आस्था को बरकरार रखने की गारंटी मिले। संविधान के आदर्शों के मुताबिक अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का हक मिले।

हर भारतीय को भारतीय संविधान की बुनियाद पर कानून का शासन कायम करने की मांग पूरे ज़ोर-शोर से उठानी होगी। पूरे हक़ के साथ। पूरी संजीदगी से संविधान के मूल्यों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों से जूझना होगा।

भारत वो देश है जहां संवाद, असहमति और मतभेद के सम्मान की परंपरा रही है। अपनी इस विरासत और हक को एक बार फिर मुट्ठी में लेने का वक्त है। ये छीन लिए जाएं, इससे पहले ही हम चेत जाएं, तभी अराजकता का ये माहौल एक सुखद शान्ति के माहौल में तब्दील हो सकता है।

जब गुंडे आपकी व्यक्तिगत आज़ादी छीन लें। जिंदगी और रोज़ी-रोटी छीन लें और इसे डर और आतंक के एक माहौल के ज़रिये जायज़ ठहरा दिया जाए तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य ज़िम्मेदार है। आवाम की गरिमा बरकरार रखने की गारंटी कौन लेगा। निश्चित तौर पर यह भूमिका राज्य की बनती है। अराजक तत्वों की हिंसा के शिकार लोगों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इसकी एक मात्र ज़िम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह यह माने कि हिंसा के शिकार लोगों के हक़ छीने गए हैं। इस देश को और इसके लोगों को आज उन ताकतों से खतरा है, जिन्हें संविधान के मूल्यों की परवाह नहीं है।

जो लोग आज सत्ता में हैं वे नफरत और लोगों में दरार पैदा कर राज चला रहे हैं। समानता, आज़ादी और भाईचारे की उन्हें कोई परवाह नहीं है।

साथियो! यह सभी मुद्दे निसंदेह ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके खिलाफ हमें एकजुटता बनाकर सरकार को चुनौती देनी ही होगी। लेकिन हमें उन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, जिन्हें दबाने के लिये राजसत्ता धर्म और जातियों के आधार पर एक अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। बुनियादी मुद्दे जैसे शोषित वर्गों के भूमि, जल, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ, आजीविका और महिलाओं के अधिकार जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े दलित, आदिवासी, पसमांदा मुस्लिम व अन्य वंचित तबके सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर देशभर में एक लंबे समय से बड़े पैमाने पर बहुत से जनांदोलन भी चल रहे हैं। दरअसल इन बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिये एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे हिन्दोस्तान की साझी शहादत-साझी विरासत वाली संस्कृति को ध्वस्त करके एक नई प्रतिक्रियावादी विचारधारा वाली संस्कृति को थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश में एक द्वेषपूर्ण सांस्कृतिक माहौल तैयार किया जा रहा है।

मोदी सरकार देश में कारपोरेट पूंजी की तानाशाही स्थापित करने में लगी है। कारपोरेट पूंजी की तानाशाही को स्थापित करने और किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और आम नागरिकों के अधिकारों पर हमला करने के लिए ही हिन्दुओं की भावनाओं का उपयोग किया जा रहा है। गौ-रक्षा के नाम पर किसान और मजदूरों को मवेशी रखने की अधिकार छीने जा रहें है सर ए आम उनकी निर्मम हत्याएं किये जा रहें है। यह सरकार जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी तो है ही साथ ही इसकी हिन्दुत्व की राजनीति उदार हिन्दु भावनाओं के विरूद्ध भी है।

एक तरफ मोदी सरकार कारपोरेट के पक्ष में काम कर रही है और कारपोरेट पूंजी को मजबूत करने में लगी हुई है वहीं वह गरीब गुरबों के लिए काम करने वाली सरकार के रूप में जनता के सामने अपने को पेश कर रही है। जबकि मोदी सरकार के दौर में किसानों की आत्महत्या की रफ्तार बढ़ी है लेकिन सरकार के पास आत्महत्या से निपटने की कोई कृषि नीति नहीं है। सभी लोग जानते है कि डब्लूटीओं के नियमों से बंधे होने के कारण विदेशी उपज हमारे बाजार में भरा पड़ा है। किसानों को बाजार की मार झेलनी पड़ रही है। डब्लूटीओं से बाहर आने का साहस भी मोदी सरकार नहीं दिखा सकी। जब तक किसानों के लिए कृषि के लागत मूल्य को नहीं घटाया जाता, उन्हें फसल रखने और विपणन की आधारभूत सुविधाएं नहीं दी जाती, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जाता, लागत का डेढ़ गुना मूल्य उनकी उपज का नहीं दिया जाता तब तक किसानों को ऋण और आत्महत्या के दुष्चक्र से बचाना बेहद मुश्किल होगा। लाखों करोड़ों रूपया कारपोरेट को सब्सिड़ी देने वाली केन्द्र सरकार किसानों की कर्ज माफी पर ईमानदार नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी उ. प्र. के गरीब और सीमांत किसानों को पूरा कर्ज माफ करने के अपने वायदें से मुकर गए जबकि मार्च 2017 तक कर्ज माफ करना गरीब किसानों के लिए बेहद जरूरी था और केन्द्र सरकार के बजट पर इसका अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता।

हाल के वर्षों में शिक्षा का निजीकरण के कारन, भारत के विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले आधे या दो तिहाई स्टूडेंट्स पहली पीढ़ी के पढ़ाई-लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एमफिल और इस तरह का शिक्षण जिससे इंसान की नागरिक समझ बढ़ती है, वह दरवाज़े ही बंध किये जा रहें है. यूजीसी की ओरसे एमफिल और पीएचडी की सीटें, बिना कोई विचार विमर्श, कम की गयी। BHU में एक ख़ास किसम का पुलिस राज आ चूका है. JNU, HCU, BBAU (बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ) अल्लाहाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय, काश्मीर, आसाम, भारत के हर इलाके में यह मोदी सरकार के कदमों के विरुद्ध, नवजवान संघर्ष कर रहे है।

कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की नीतियों की वजह से बेइंतहा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। जनता के न्याय प्राप्त करने और बेहतर प्रशासन प्राप्त करने की सहज भावनाओं का भाजपा दुरूपयोग कर रही है। उ. प्र. में अवैध बूचड़खाने बंद करने की उसकी नीति जनता के प्रति किसी सहज प्रेम का भाव नहीं है बल्कि मांस उद्योग को बड़े पूंजी घरानों के हवाले करने की नियत से किया गया है। जो लोग छोटेस्तर के व्यवसाय के बतौर इसमें लगे हुए थे उन्हें बूचड़खानों से ही मछली और चिकन तक खरीद कर उसे बाजार में बेचना पड़ेगा। मांस उद्योग को बंद करने की मंशा मोदी सरकार की कतई नहीं है। वह इस व्यवसाय को बड़ी पूंजी के हवाले करना चाहती है। नोटेबंदी करके समस्त परंपरागत उत्पादन व्यवस्था और व्यापार पर सीधा हमला किये जा रहें है।

दरअसल पूंजी का केन्द्रीकरण और विस्तार कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए मोदी सरकार कर रही है। इससे खेती किसानी, छोटे मझोले व्यवसाय और उद्योग चौपट हो रहे है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक कल्याण के मदों में बराबर कटौती की जा रही है। हमें इस सरकार के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, गरीब व आम नागरिक विरोधी चेहरे को जनता के सामने लाना होगा और लम्बे संघर्षो के बदौलत हासिल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक एकता निर्मित करनी होगी।

इसलिए दोस्तो ! उठिये, एक बार फिर साथ उठिये और नफरत और विध्वंस की इन ताकतों के खिलाफ पूरे जुनून के साथ मैदान में उतर पड़िये। इन ताकतों के सामने अपने पूरे फौलादी इरादों के साथ डट जाइए। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, इन नापाक इरादों से लड़ने का सामान तैयार कर लीजिये।

हक़ और इंसाफ के लिए और इंसानियत को क़ायम रखने के लिए एक शसक्त अभियान की शुरुआत करनी होगी जिसे सभी संगठन सामूहिक जिम्मेदारी से चलाएंगे। इस अहम् फैसलें को तय करने हेतु 10 मई के दिन लखनऊ में एक प्रतिनिधी सम्मलेन आयोजित की जा रही है।

आप सभी साथीगण सादर आमन्त्रित है। स्थान: गाँधी भवन, रेजीडेंसी रोड, कैसरबाग़ लखनऊ। समय : सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।

आईए हाथ उठायें हम भी
हम जिन्हें रस्म-ए-दुआ याद नहीं
हम जिन्हें सोज़-ए-मुहब्बत के सिवा
कोई बुत कोई खुदा याद नहीं
जिनके सर मुन्तज़िर-ए-तेग-ए-जफ़ा हैं उनको
दस्त-ए-क़ातिल को झटक देने की तौफ़ीक मिले
आईए हाथ उठायें हम भी, हम जिन्हें रस्म-ए-दुआ याद नहीं

-फ़ैज़ अहमद "फ़ैज़"

आल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, आल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन, आल इंडिया सेक्युलर फोरम, अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन, अमन बिरादरी, आंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट्स यूनियन, अनहद, अंक फाउंडेशन, अस्मिता चाइल्ड लाइन, अस्मिता (Association for the Socially Marginalised Integrated Therapeutic Action), बकरा गोश्त व्यापार मंडल लखनऊ, भारतीय महिला फेडरेशन, भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन, भूमि अधिकार आन्दोलन, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, क्रिस्चियन वेलफेयर एसोसिएशन, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, कॉर्ड (CORD) डॉ. रही मासूम रज़ा साहित्य अकादमी, फैथ इन एक्शन, एफ.ई.ई.डी. ग्रामीण खेतिहर मजदूर यूनियन, गुमटी व्यावसायिक कल्याण समिति, इन्साफ, इप्टा यू.पी., जन संस्कृति मंच यू.पी., जॉइंट एक्शन कमिटी बी.एच.यु., महाभूमि वी.एस.एस., मजदूर किसान शक्ति संगठन, नेशनल अलायन्स फॉर पीपल'स मूवमेंट्स (NAPM), नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR), एन.टी.यू..ई., न्याय मंच यू.पी., पीपल'स एडवोकेसी फोरम, पीपल'स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) यू.पी., पी.वी.सी.एच.आर., कौमी एकता फोरम, राईनी महासभा, रिहाई मंच,. साझी दुनिया, सनातकदा सामाजिक पहल, सावित्रीबाई फुले समिति, स्त्रीमुक्ति संगठन इलाहबाद, स्टूडेंट्स फॉर चेंज बी.एच.यु., यू.पी. जन मंच, यू.पी. यूनाइटेड पास्टर्स कमिटी कानपुर, यू.पी. वर्कर्स फ्रंट, यूनाइटेड क्रिस्चियन फोरम ट्रस्ट, यूनाइटेड क्रिस्चियन फोरम, विश्व ज्योति संचार केंद्र